



स्वच्छ भारत अभियान का महत्त्व और प्रभाव: एक समीक्षात्मक अध्ययन

डॉक्टर बबीता

सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग
बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी अस्थल बोहर ,रोहतक

आजाद सिंह

राजनीतिक विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय अस्थल, बोहर रोहतक

DOI : <https://doi.org/10.36676/urr.v11.i2.1274>

Published: 21/06/2024

*Corresponding Author

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में एसबीएम भारत क्रियाविशन का आधा सफर हम तय कर चुके हैं। इसमें काफी गति आयी है और महत्वपूर्ण सफलताएं भी मिली हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री ने पहली बार लाल किले की प्राचीर से इस अभियान की शुरुआत की थी, तब से अब तक यह धीरे-धीरे एक जन-आंदोलन का रूप ले चुका है। 2 अक्टूबर, 2014 को इस कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक ग्रामीण स्वच्छता भारत में सफाई व्यवस्था 42 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। ग्रामीण भारत में खुलेमें शौच करने वाले लोगों की संख्या 55 करोड़ से घटकर 35 करोड़ तक हो गयी है। 1,90,000 गांव, 130 जिले और तीन राज्य पूरी तरह खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) हो चुके हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2 अक्टूबर, 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त देश बनाना है।

स्वच्छता को प्राथमिकता देना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। स्वच्छता की कमी ही पांच साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया जैसी समस्या का मुख्य कारण है। इसी के कारण कई बच्चों की जान भी चली जाती है, जिनको बचाया जा सकता है। स्वच्छता महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए भी जरूरी है। भारत जहां आर्थिक शक्ति बनने की तरफ कदम आगे बढ़ा रहा है, वहां खुले में शौच के चलन को खत्म करना बेहद अनिवार्य है।

भूमिका

स्वच्छ भारत अभियान

निर्मल भारत अभियान जैसे कई जागरूकता कार्यक्रमों को निजी स्वच्छता और पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए शुरू किया गया था जिससे भारत में फैली हर प्रकार की गंदगी को दूर किया जा सके और गांधीजी के सपने को साकार किया जा सके। भारत के नागरिकों के अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण, ये सभी ड्राइव एक मजबूत प्रभाव बनाने में विफल रहे। भारतीयों ने एक अस्वस्थ और गंदे जीवनशैली का नेतृत्व करना जारी रखा। वास्तव में भारत को स्वच्छ बनाने के लिए केवल गांधी के चश्मे के ढांचे से काम चलने वाला नहीं है। इसके लिये गांधी की सोच पर सम्पूर्णता से विचार किये जाने एवं उसको क्रियान्वित करने की जरूरत है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एवं गांधीजी के सपने को वास्तविक रूप से साकार करने के लिए महात्मा गांधी के स्वच्छता अभियान को एक बार फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 सितम्बर 2014 को केन्द्रीय मंत्रीमण्डल की मंजूरी से निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत अभियान के रूप में पुनर्गठित किया एव स्वच्छ भारत अभियान नाम के तहत राजघाट, नई दिल्ली में 2 अक्टूबर 2014 को दोबारा शुरू किया। यह कार्यक्रम अगले पांच वर्षों में 2 अक्टूबर, 2019 तक पूरा किया जाना है। इस स्वच्छ भारत अभियान को एक कदम स्वच्छता की ओर नारा दिया गया है। स्वच्छ भारत अभियान को क्लीन इंडिया मिशन या क्लीन इंडिया ड्राइव भी कहा जाता है। स्वच्छ भारत अभियान भारत में सबसे बड़ी स्वच्छता अभियान माना जाता है। यह सरकार द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है जो राष्ट्र के पिता (बापू) के दृष्टिकोण को पूरी तरह से विश्व स्तर पर सफल बनाने के लिए काम करता है।

इसके लिए भारत सरकार ने महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ (2 अक्टूबर 2019) तक ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके भारत को खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। यह शहरी व ग्रामीण लोगों के लिए मांग आधारित जन केन्द्रित अभियान है जिसमें लोगों की स्वच्छता सम्बन्धी आदतों को ओर बेहतर बनाया जा सके, स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की मांग उत्पन्न करना और स्वच्छता सुविधाओं को उपलब्ध कराना, जिससे आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। इस अभियान में शौचालयों का निर्माण करवाना, पीने का साफ





पानी हर घर तक पहुंचाना, सड़कों की सफाई करना और देश का नेतृत्व करने के लिए देश के बुनियादी ढांचे को बदलना सड़कों और फुटपाथों की सफाई, अनाधिकृत क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाना शामिल है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत का निर्माण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अस्वच्छ भारत की तरवीरें भारतीयों के लिए अक्सर शर्मिंदगी की वजह बन जाती हैं। इसलिए स्वच्छ भारत के निर्माण एवं देश की छवि सुधारने का यह सही समय एवं अवसर है।

दिल्ली में राजपथ पर स्वच्छ भारत अभियान की औपचारिक शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने का आह्वान करते हुए भारत माता के दो महान सपूतों महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्होंने याद दिलाया कि कैसे श्री शास्त्री द्वारा प्जय जवान, जय किसान का नारा दिए जाने के बाद किसानों ने कड़ी मेहनत की और देश को खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि राष्ट्रपिता ने क्विट इंडिया और क्लीन इंडिया का नारा दिया था लेकिन अभी भी बापू का क्लीन इंडिया का सपना अधूरा है। मोदीजी का मानना है कि यदि हम इस अभियान को पूरा कर दिखाते हैं तो ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस प्रकार भारतीय लोगों ने एकजुट होकर भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया था उसी प्रकार अब भी हमें एक होने की सख्त जरूरत है और यदि इस अभियान के लिए प्रतिवर्ष देश का हर नागरिक अपने कीमती समय में 100 घंटे भी सफाई के लिए निकालता है तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत स्वच्छ और खुशहाल बन जाएगा। उन्होंने एक मंत्र दिया की हम न गन्दगी खुद करेंगे और न दूसरों को करने देंगे।

प्रधानमंत्री ने देश की सभी पिछली सरकारों और सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा सफाई को लेकर किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत को स्वच्छ बनाने का काम किसी एक व्यक्ति या अकेले सरकार का नहीं है। यह काम तो देश के 125 करोड़ लोगों द्वारा किया जाना है जो भारत माता के पुत्र-पुत्रियां हैं। उन्होंने ये भी निवेदन किया कि हर भारतीय को इस अभियान को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए और इस अभियान को सफल बनाने में अपनी तरफ से परी कोशिश करे।

स्वच्छ भारत अभियान का महत्व

स्वच्छ भारत मिशन को भारत में तब तक लगातार चलाना बहुत जरूरी है जब तक कि इसके लक्ष्य साकार न हो जाएं। भारत में लोगों को वास्तव में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक कल्याण की अनुभूति प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। यह वास्तविक अर्थों में भारत में जीवन स्तर को उन्नत बनाना है जिसकी शुरुआत सर्वत्र स्वच्छता लाकर की जा सकती है। भारत में खुले में शौच को खत्म करने के साथ-साथ सभी को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना वाकई बहुत जरूरी है।

मिशन की आवश्यकता

1. भारत में अस्वच्छ शौचालयों को पलशिंग शौचालयों में बदलने की आवश्यकता है।
2. मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए ये जरूरी है।
3. इसका उद्देश्य नगरपालिका ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रक्रियाओं, स्वच्छ निपटान, पुनरुपयोग और पुनर्चक्रण के माध्यम से उचित अपशिष्ट प्रबंधन को लागू करना है।
4. यह व्यक्तिगत स्वच्छता के रखरखाव और स्वस्थ स्वच्छता विधियों के अभ्यास के संबंध में भारतीय लोगों के बीच व्यवहारिक परिवर्तन लाना है।
5. यह करने के लिए हैग्रामीण इलाकों में रहने वाली आम जनता के बीच वैश्विक जागरूकता पैदा करना क्षेत्र और इसे लिंक करें जीम सार्वजनिक स्वास्थ्य।
6. इसका उद्देश्य अपशिष्ट निपटान प्रणालियों को डिजाइन, निष्पादित और संचालित करने के लिए कार्यशील निकायों का समर्थन करना है स्थानीय स्तर पर।
7. यह पूरे भारत में स्वच्छता सुविधाएं विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी लाना।
8. यह करने के लिए भारत को स्वच्छ और हरित भारत बनायें।
9. के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना आवश्यक ग्रामीण क्षेत्रों में लोग।





10. इसका उद्देश्य समुदायों और पंचायती को प्रेरित करके स्थायी स्वच्छता प्रथाओं को लाना है राज संस्थाएँ स्वास्थ्य शिक्षा जैसे जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से।

11. यह करने के लिए वास्तव में बापू के सपने को साकार करें।

शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन

शहरी क्षेत्रों के स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य लगभग 1.04 करोड़ घरों को कवर करना है उन्हें 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय, 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय एक साथ उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ। सामुदायिक शौचालय बनाने की योजना बनाई गई है आवासीय क्षेत्रों में निर्मित जहां व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की उपलब्धता कठिन है और बस स्टेशनों, पर्यटक स्थलों, रेलवे स्टेशनों सहित निर्दिष्ट स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय, बाजारों आदि शहरी क्षेत्रों (लगभग 4,401 कस्बों) में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया है 2019 तक पांच वर्षों में पूरा करने की योजना है। कार्यक्रमों की लागत रुपये की तरह निर्धारित की गई है ठोस पर 7,366 करोड़ अपशिष्ट प्रबंधन विभाग, 1,828 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है 655 करोड़ रुपये सामुदायिक शौचालय, व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों पर 4,165 करोड़ रुपये आदि कार्यक्रम इसका उद्देश्य गंदे शौचालयों को शौचालयों में परिवर्तित करके पूर्ण खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करना है पलश शौचालय, हाथ से मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन, जनता के व्यवहार में परिवर्तन लाना, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।

ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन

ग्रामीणस्वच्छभारत मिशन देश में स्वच्छता कार्यक्रमों को लागू करने वाला एक मिशन है ग्रामीण इलाकों। इससे पहले निर्मल भारत अभियान (जिसे संपूर्ण स्वच्छता अभियान, टीएससी भी कहा जाता है) 1999 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों को बनाने के लिए हालांकि अब इसे साफ करें स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में पुनर्गठित किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य है 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त बनाना जिसके लिए लागत का अनुमान लगाया गया है लाख चौतीस हजार करोड़ रुपये के लिए लगभग 11 करोड़ 11 लाख का निर्माणप्रसाधन देश में। कचरे को जैव उर्वरक और उपयोगी ऊर्जा में बदलने की बड़ी योजना है प्रपत्र. इस मिशन में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और की भागीदारी शामिल है जिला परिषद निम्नलिखित हैं

उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन के बारे में नीचे संक्षेप में बताया गया है

1. ग्रामीणक्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना।
2. स्वच्छ के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को प्रेरित करें 2019 तक भारत.
3. स्थानीय कार्य निकायों (जैसे समुदाय, पंचायत और राज संस्थान आदि) को प्रेरित करना उपलब्ध करायेँ स्थायी स्वच्छता सुविधाओं की आवश्यकता है।
4. समुदाय द्वारा प्रबंधनीय उन्नत पर्यावरणीय स्वच्छता प्रणालियाँ विकसित करना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना।
5. ग्रामीण क्षेत्रोंमें पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित और टिकाऊ स्वच्छता को बढ़ावा देना।

अध्ययन के उद्देश्य

1. स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जानना
2. स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्यों के बारे में जानना

शोध प्रविधि – यह शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है जिसके लिए पुस्तकों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध जर्नल में प्रकाशित शोध पत्रों का अध्ययन किया गया है तथा विभिन्न समाचार पत्रों व पुस्तकों से आंकड़ों को इकट्ठा किया गया है। इस प्रकार शोध पत्र हेतु विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

साहित्य समीक्षा

1. संजय श्रीवास्तव (2020) प्रस्तुत लेख में बताया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण वर्ष 2024–25 तक के स्व लिए शुरू हो चुका है, इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसमें पहले चरण में रह गए स्वच्छता के कामों को जहां दुरुस्त किया जाएगा, वहीं अगर गांवों में कोई घर अब भी निजी शौचालय बनवाने से छूट गया है, तो उसे पूरा किया जाएगा। उसके लिए सरकार की वित्तीय मदद भी जारी रहेगी।





स्वच्छ भारत मिशन अभियान जब 02 अक्टूबर, 2014 में शुरू हुआ था तो ग्रामीण स्वच्छता में हम बहुत पीछे थी। अगले पांच सालों में ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान साबित हुआ। जब वर्ष 2018-19 में इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ तो पता लगा कि इस अभियान से गांवों में बीमारियों की संख्या में तेजी से कमी हुई है। इसका स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ा है। इस सर्वे को संसद में भी पेश किया गया। इसे पेश करते हुए वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बताया कि आजादी के 67 सालों बाद जब वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया।

2. परमेश्वर अय्यर (2020) स्वच्छ भारत मिशन रू साझा दायित्व, प्रस्तुत लेख में बताया गया है कि पहले के समय में चलने वाले स्वच्छता कार्यक्रमों की तरह स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ शौचालय निर्माण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह व्यावहारिक रूप से जनता में बदलाव लाने वाला आंदोलन है। सड़क, पुल या एयरपोर्ट बनाना फिर भी आसान है, लेकिन इंसान के व्यवहार को बदलना काफी मुश्किल और जटिल मुद्दा है। अगर आप 50 करोड़ से ज्यादा लोगों की खुले में शौच की इस आदत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो वर्षों से उनके साथ है, तो यह एक बहुत बड़ा कार्य है।

हालांकि जनसंचार अभियान उपयोगी साबित होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इस व्यावहारिक बदलाव को लाने के लिए प्रशिक्षित लोगों की जरूरत है। ये लोग गांवों में जाकर वहां के लोगों से बातचीत करके साफ-सफाई और शौचलाओं की अहमियत के बारे में बता सकते हैं। देशभर के राज्यों और जिलों में इस तरह के प्रशिक्षित प्रोत्साहनकर्ताओं की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन इसमें और बढ़ोतरी की जरूरत है।

3. पंकज के सिंह द्वारा लिखित पुस्तक स्वच्छ भारत समृद्ध भारत (2017), में स्वच्छता को मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्व का विषय स्वीकार करते हुए यह कहा गया है कि किसी भी देश के बेहतर और विकसित देश होने के पीछे वहां के निवासियों में स्वच्छता के प्रति अनुशासित और सक्रिय बने रहने की भावना होना आवश्यक है। अधिकांश विकसित देशों में छोटी आयु से ही बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है जो हमारे देश में तुलनात्मक रूप से कम है। स्वच्छ भारत अभियान इस दिशा में निश्चित रूप से और बेहतर रूप में कार्य कर सकता है।

4. प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार ने भी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान द्वारा लोगों में आए बदलाव को अपनी पत्रिका स्वच्छ भारत ए सक्सेस स्टोरी (2017), के माध्यम से रेखांकित किया है।

5. मृदुला सिन्हा और आर. के. सिन्हा ने भी अपनी पुस्तक स्वच्छ भारत ए क्लीन इंडिया (2016), में स्वच्छता की प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए यह बताया है कि स्वच्छ भारत अभियान इस दिशा में एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है।

6. किरण बेदी और पवन चौधरी द्वारा लिखित पुस्तक स्वच्छ भारत चेक लिस्ट (2015), के अंतर्गत स्वच्छता को प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बताते हुए यह बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक अपने द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाकर स्वच्छ भारत अभियान में अपना अमूल्य योगदान दे सकता है।

7. श्रीराम वर्मा ने अपनी पुस्तक भारतीय राजनीतिक विचारक में यह बताया है कि गांधीजी स्थानीय स्वशासन के समर्थक थे। गांधीजी ने पंचायती राज की जो संकल्पना प्रस्तुत की है उसके अंतर्गत उन्होंने स्वच्छता और निर्मलता को महत्वपूर्ण आधार माना है।

8. मधुकर श्याम चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक भारतीय राजनीतिक विचारक में स्वच्छता को गांधी दर्शन का महत्वपूर्ण आधार स्वीकार किया गया है। इसमें बताया गया है कि गांधी जी ने अपने समाचार पत्रों और पुस्तकों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश हर भारतीय नागरिक को देने का प्रयास किया।

सरकार के प्रयास

2 अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह अभियान शुरू किया तब उनके साथ कई राजनेता, उद्योगपति, बॉलीवुड कलाकार सहित पूरे देश में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षक, छात्र और सरकारी कर्मचारी स्वच्छता से इस स्वच्छ भारत अभियान में शामिल हुए। इसे जनआंदोलन बनाने के लिए, स्वच्छ भारत अभियान में योगदान देने और सोशल मीडिया पर इसे साझा करने के लिए उन्होंने नौ हस्तियों को आमंत्रित किया है, जिनमें मृदुला सिन्हा, सचिन तेंदुलकर, बाबा रामेदव शशि थरूर अनिल अंबानी कमल हसन सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा और टेलिविजन कार्यक्रम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन कार्यों को अंजाम देने के लिए नौ अन्य लोगों को आमंत्रित किया गया है और इस तरह एक श्रृंखला-सी बना दी गई है। इस प्रकार इससे लोग जुड़ते जाएंगे। प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों को स्वच्छता से स्वास्थ्य की अहमियत को समझाते हुए हर देशवासी से इसे अपनाने की अपील की थी। उनके इस कदम से स्वच्छता जैसा





उपेक्षित विषय अचानक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया। इस मुहिम में राज्यों ने भी भाग लिया है और कई अन्य कार्यक्रम और योजनाएं इस अभियान को सफल बनाने के लिए तैयार की जा रही हैं। हर साल सरकार देश भर से साफ शहरों की सूची जारी की जा रही है ताकि सभी शहरों में खुद को अधिक से अधिक स्वच्छ एवं बेहतर बनाने हेतु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके। अधिकांश राज्यों ने राज्य या सरकारी कार्यालयों में तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बहुत से स्कूलों और कॉलेजों ने इस अभियान में दिलचस्पी दिखाई है और वे इसे प्रभावी रूप से लागू कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के तहत स्वच्छ पखवाड़ा मनाने के साथ, प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय ने एक स्वच्छता एक्शन प्लान बनाया है।

सरकार घरों में शौचालय बनाने के लिए लोगों को सब्सिडी दे रही है। व्यवहार में बदलाव और उपयुक्त तकनीकों के इस्तेमाल से आगे जरूरी है कि स्वच्छता सबका दायित्व बने। इसके लिए निजी क्षेत्र भी स्वच्छता अभियान में तेजी से शामिल हो रहे हैं। इसका एक उदाहरण टाटा समूह के प्रयास हैं। इसने भारत के प्रत्येक जिले में नियुक्त 600 युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक मदद दी है, जिससे कि स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने वाले कलेक्टरों को सहयोग किया जा सके।

स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन में काफी गति आयी है और महत्वपूर्ण सफलताएं भी मिली हैं। 2 अक्टूबर, 2014 को इस कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक ग्रामीण स्वच्छता भारत में सफाई व्यवस्था 42 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। ग्रामीण भारत में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या 55 करोड़ से घटकर 35 करोड़ तक हो गयी है। भारत में अक्टूबर 2014 एवं नवम्बर 2017 के बीच घरों में 52 मिलियन शौचालय बनवाए गए हैं। पिछले 4 वर्षों में देश के पिछड़े इलाकों के कई गांव खुले में होने वाले शौच से बिल्कुल ही मुक्त हो गए हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री ने पहली बार लाल किले की प्राचीर में इस अभियान की शुरुआत की थी, तब से अब तक यह धीरे-धीरे एक जन-आंदोलन का रूप ले चुका है।

स्वच्छता के मामले में आज गांव, नगर, शहर और कस्बे सभी स्थान पर स्वच्छ भारत मिशन का अभियान पहुंच रहा है। इससे आम और खास दोनों तरह के लोगों में स्वच्छता का विचार पनप रहा है और इस अभियान के कारण देशभर के बहुत सारे क्षेत्रों में साफ-सफाई के प्रति जागरूकता फैली है।

ग्रामीण भारत में स्वच्छता की समस्याएं

विकसित देशों में मानव मल के स्वच्छता से निपटान का मानक तरीका सीवरेज है। वित्तीय अड़चनों और संचालन व रखरखाव की भारी लागत की वजह से फिलहाल भारत में मानव मल के प्रबंधन की समस्या के समाधान का तरीका सीवरेज प्रणाली नहीं है। विकासशील देशों में न तो सरकार और न स्थानीय निकाय या लाभार्थी सीवेज प्रणाली के रखरखाव और संचालन की पूरी लागत का खर्च उठा सकते हैं। इसके अलावा लम्बे समय तक रखरखाव और संचालन के लिए कुशल व्यक्तियों और अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह सेप्टिक टैंक प्रणाली भी महंगी है और इसमें मानव मल को बहाने के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत होती है। इसके अलावा समय-समय पर सफाई कराने और कचरे के निपटान की अन्य समस्याएं भी हैं। अपशिष्ट जल-मल के निपटान की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण मच्छर पैदा होते हैं, बदबू उठती है और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

तकनीकी उपाय

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी उपायों से ही साफ-सफाई की समस्या का समाधान हो सकता है। इसके लिए सुलभ न किफायती लागत वाली एक-दो गड्ढे वाली क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जिसमें पानी उड़ेल कर मानव मल को बहाया जाता है।

अनुकूल, तकनीकी लिहाज से उपयुक्त, सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से स्वीकार्य और आर्थिक दृष्टि से किफायती शौचालय हैं। यह स्वदेशी टेक्नोलॉजी है और इस तरह के शौचालयों का निर्माण स्थानीय मजदूरों और सामग्री की मदद से आसानी से किया जा सकता है। इसमें मल के उत्पन्न होने के स्थान पर ही मानव मल का सुरक्षित तरीके से निपटान कर दिया जाता है जिससे स्वास्थ्य संबंधी फायदे मिलते हैं। इसमें एक बर्तन होता है जिसकी तली की ढलान 25-28 डिग्री तक होती है और इसमें विशेष रूप से बनाया गया 20 मिलीमीटर का ट्रेप वॉटर सील का काम करता है। इसमें मानव मल को बहाने के लिए सिर्फ एक लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है जिससे यह पानी के संरक्षण में मदद करता है।





इस तरह के शौचालय के गड्डों को साफ करने के लिए सफाई मजदूर की जरूरत भी नहीं होती। शौचालय में दो गड्डे होते हैं जिनका आकार स्थान और उपयोग करने वालों की संख्या के अनुसार अलग-अलग होता है। प्रत्येक गड्डे को आमतौर पर तीन साल के उपयोग के लिए बनाया जाता है। दोनों गड्डे बारी-बारी से इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जब एक गड्डा भर जाता है तो बहाए जाने वाले मल को दूसरे गड्डे की ओर मोड़ दिया जाता है। करीब दो साल में पहले गड्डे का कचरा सड़ कर सूख जाता है और खाद बन जाता है। हानिकारक जीवाणुओं से मुक्त हो जाने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सड़ा हुआ कचरा गंधहीन होता है और अच्छी खाद तथा जमीन को सुधारने का काम करता है। इसे खोद कर आसानी से निकाला जा सकता है और खेती में इस्तेमाल किया जा सकता है। गड्डे को खाली कराने की लागत को उससे निकलने वाली खाद की कीमत से कुछ हद तक वसूल हो जाती है। सुलभ शौचालयों को मकानों की ऊपरी मंजिलों में भी बनाया जा सकता है। इसमें सुधार करने की पर्याप्त गुंजाइश होती है और बाद में जरूरत पड़ने पर इसे सीवर लाइन से जोड़ा जा सकता है। सुलभ ने अब तक देश के विभिन्न भागों में 15 लाख से ज्यादा व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए हैं।

समीक्षा

काम पूरा हो जाने पर प्रगति की समीक्षा बैंक, लाभार्थी, कार्यान्वयन एजेंसी और समन्वय एजेंसी द्वारा मिलकर की जानी चाहिए। लाभार्थी तथा निर्माण करने वाली एजेंसी द्वारा दस्तखत किया गया पूर्णता प्रमाणपत्र बैंक को भेजा जाएगा और बैंक किए गए काम की जांच के बाद धनराशि का समायोजन करेगा।

- पहले 10 प्रतिशत परिवार जिनके घरों में शौचालय नहीं हैं उन्हें सहायता से बाहर रखा गया है क्योंकि यह माना गया है कि वे पैसे वाले लोग हैं।

- करीब 5.4 करोड़ परिवारों को 1986 से सहायता या सब्सिडी पहले ही दी जा चुकी है जब शौचालय की लागत 500 रुपये प्र हुआ करती थी। हालांकि इनमें कुछ प्रतिशत ऐसे भी हैं जिनके यहां शौचालय या तो हैं ही नहीं या फिर चालू हालत में नहीं हैं। सरकार को चाहिए कि वह उन्हें नए सिरे से सब्सिडी दे, अन्यथा वे तीन साल के भीतर अपने घरों में शौचालय नहीं बना पाएंगे।

इस समय भारत सरकार प्रति शौचालय 12,000 रुपये का ऋण दे रही है जिससे अच्छी गुणवत्ता वाला शौचालय बनाना संभव नहीं है। इसलिए इसके लिए 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाना चाहिए जिससे वे अपनी पसंद का शौचालय बना सकें और लक्ष्य पूरा हो सके।

अगर सरकार 30 हजार रुपये की सब्सिडी दे तो शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने की पूरी संभावना है।

- भारत में 675 जिले, 6849 ब्लॉक, 2.51 लाख पंचायतें और 6.46 लाख गांव हैं। हमारे यहां 16057 कंपनियां हैं जिनका सालाना मुनाफा 500 करोड़ रुपये से अधिक है। ये कंपनियां अपनी क्षमता के अनुसार एक गांव या एक पंचायत या एक ब्लॉक या एक जिले को शौचालयों के निर्माण के लिए अपना सकती हैं।

- हमने शौचालय की लागत 30,000 रुपये रखने का जो अनुमान लगाया है वह अगले तीन सालों, यानी 2019 तक निर्माण सामग्री की कीमतों में अवश्यभावी बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर लगाया है। यानी कंपनी को एक शौचालय के निर्माण के लिए उसकी लागत के कम से कम 30,000 रुपये देने होंगे। अगर किसी गांव में 200 शौचालय बनाने हैं तो लागत 60 लाख रुपये आएगी। तीन गांवों वाली पंचायत के लिए यह लागत 1.8 करोड़ रुपये होगी। इसी तरह किसी ब्लॉक या तहसील को इसके दायरे में लाने के लिए 60 करोड़ रुपये और जिले के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। भारती फाउंडेशन ने पंजाब के एक जिले लुधियाना में इस अभियान का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली है। कंपनी को फ़ैसला करना है कि वह एक शौचालय का निर्माण करेगी या एक गांव, एक पंचायत, एक ब्लॉक और एक जिले में सभी शौचालयों का निर्माण करेगी। यह काम कंपनी या संगठन के नाम से किया जाएगा। निर्णय करने से पहले कंपनी गांव के उन लोगों के साथ बातचीत करना चाहेगी जिनके लिए वह शौचालयों का निर्माण करने जा रही है।

निष्कर्ष

स्वच्छ भारत मिशन का एक अहम तत्व नतीजों का प्रमाणीकरण भी है। यह इस कार्यक्रम की विश्वसनीयता के लिए बहुत जरूरी है। वर्तमान में जिला-स्तर, राज्य-स्तर

■ और राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय पक्ष सत्यापन के साथ एक बहुस्तरीय प्रक्रिया चल रही है। इन प्रयासों को और मजबूत बनाए जाने की जरूरत है और आने वाले दिनों में मुख्यधारा में शामिल करने की जरूरत है।





इसके अलावा खुले में शौच से मुक्ति का इसलिए भी अहम है, क्योंकि इसकी – उपलब्धि अन्य सरकारी कार्यक्रमों की तरह किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं – है। ओडीएफ का दर्जा पाना एक मसला है, लेकिन स्थानीय संरचनाओं के जरिये बनाए रखना दूसरा मसला है। मंत्रालय द्वारा राज्यों के साथ एक संपोषणीयता प्रोटोकॉल – विकसित किया गया है और इसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने की जरूरत है। मंत्रालय के पास भी एक मजबूत सूचना प्रबंधन तंत्र (एमआईएस) है, जोकि स्थानीय स्तर पर प्रत्येक परिवार की प्रगति का ब्यौरा रखता है। स्वच्छ एप के साथ एमआईएस भी सार्वजनिक है। प्रभावी ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन भी इस अभियान का अहम हिस्सा है। देश के विभिन्न गांवों में अपशिष्ट प्रबंधन पर काम शुरू किया जा चुका है। इनमें उन गांवों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो पहले ही खुले में शौच से मुक्त स्तर प्राप्त कर चुके हैं। ग्रामीण स्वच्छता इंडेक्स सरकार द्वारा विकसित किया जा चुका है। इसमें गांव खुद को ही संपूर्ण स्वच्छता के अनुसार अंक देते हैं और स्वच्छता की दिशा में अपनी प्रगति का आकलन करते हैं। ओडीएफ स्तर, अपशिष्ट प्रबंधन स्तर और सामान्य स्वच्छता सूचकांक किसी भी गांव को ओडीएफ तक पहुंचने में मदद करता है, जोकि ओडीएफ स्तर हासिल करने के बाद का चरण है। स्वच्छ भारत मिशन अच्छी प्रगति कर रहा है, और केंद्र और राज्य दोनों = की टीमों आगे आने वाली चुनौतियों को लेकर पूरी तरह सजग हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व – में राज्यों में राजनीतिक नेताओं, प्रशासनिक नौकरशाही, जमीनी स्तर पर सरपंच खासतौर पर महिलाओं के सहयोग से यह बात तो साफ है कि देशभर में यह आंदोलन सफल होगा।

स्वच्छता किसी और पर थोपा जाने वाला कार्य नहीं है जो किसी पर दबाव डालकर कराया जाए। अच्छी सेहत के लिए हर प्रकार की स्वच्छता जरूरी है। इसीलिए स्वच्छता के पूर्व हर एक को इसके महत्व के बारे में पता होना चाहिए। भारत के क्रमिक विकास के लिए स्वच्छ भारत मिशन बहुत ही जरूरी है जब तक कि लक्ष्य न पूर्ण न हो जाए। भारत में लोगों के लिए वास्तव में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक कल्याण की भावना को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। यह वास्तविक मायने में भारत की स्थिति की अग्रिम बनाने के लिए है।

स्वच्छ भारत मिशन का एक अहम तत्व नतीजों का प्रमाणीकरण भी है। यह इस कार्यक्रम की विश्वसनीयता के लिए बहुत जरूरी है। वर्तमान में जिला-स्तर, राज्य-स्तर और राष्ट्रीय स्तर की तृतीय पक्ष सत्यापन के साथ एक बहुस्तरीय प्रक्रिया चल रही है। इस प्रयासों को और मजबूत बनाए जाने की जरूरत है और आने वाले दिनों में मुख्यधारा में शामिल करने की जरूरत है। स्वच्छता अभियान मिशन को सहभागिता के द्वारा आगे बढ़ाना आज भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि स्वच्छता देश के प्रत्येक व्यक्ति की आदत बन जाए तो देश की कायापलट ही हो जाएगी क्योंकि अस्वच्छता के कारण आज देश भ्रष्टाचार, अनाचार, स्वार्थ, हिंसा, अधर्म और पापाचार की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देश के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी स्वच्छ रहने और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना देशभक्ति का ही कार्य है।

जैसा कि हम सभी ने सबसे प्रसिद्ध कहावत के बारे में सुना है कि स्वच्छता के आगे बुलंदी है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक स्वस्थ देश और स्वस्थ समाज को अपने नागरिकों को जीवन के हर कदम में स्वच्छ और स्वस्थ होने की आवश्यकता है। जब देश की आम जनता भी इस अभियान में सहयोग देने लगेगी तो इस अभियान को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वच्छ भारत अभियान एक बड़ी ही कारगर योजना साबित होगी जिसके जरिये लोग स्वच्छता के महत्व को अच्छी तरह से समझ पाएंगे जिसके साथ ही भारत एक सुन्दर और स्वच्छ देश बन जाएगा। यदि देश के नागरिक इस अभियान को एक जिम्मेदारी के रूप में लेते हैं तो इस अभियान को पूरा होने में कोई रोक नहीं सकता।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. नरेंद्र सिंह तोमर स्वच्छ भारत मिशनरु व्यवहार परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन तक ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ,अक्टूबर 2016
2. परमेश्वर अय्यर ग्रामीण समुदायों ने अपनाया स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, अक्टूबर 2016
3. रविंद्र सिंह ग्रामीण स्वच्छता में पंचायत की भूमिका ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ,अक्टूबर 2016





- 4 . परमेश्वर अय्यर, स्वच्छ भारत मिशन सांझा दायित्व योजना मासिक पत्रिका ,नई दिल्ली, मई 2017
- 5 . संजय श्रीवास्तव, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली, अक्टूबर 2020
6. उर्वशी प्रसाद, स्वच्छ भारत के लिए जल और स्वच्छता ग्रामीण विकास मंत्रालय ,नई दिल्ली, अक्टूबर 2020
7. स्वच्छ भारत चेक लिस्ट किरण बेदी व पवन चौधरी विस्डम विलेज पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, पृ.सं. 18, 1 जनवरी 2015
8. जोशीएस. सी., स्वच्छ भारत मिशन एन एसएसमेंट रू 1 जनवरी 2017 पृ.सं. 102
9. यंग इण्डिया, 22 जनवरी, 1930
10. कलैक्टेटेड वर्क्स ऑफ महात्मका गाँधी, खण्ड – 66, पृ.सं. 426
11. हरिजन, 12 अप्रैल, 1942
12. वर्मा, श्रीराम, इंडियन पॉलिटिकल थिंक्स कॉलेज बुक हाउस, जयपुर पं. 430 , 1998 .
- 13.चतुर्वेदी, मधुकर श्याम, प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक कॉलेज बुक हाउस, जयपुर, पृ. 301
14. नागर, पुरुषोत्तम 1999 आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक विचार, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ. 430
15. स्वच्छ भारत अभियान, एम. के. सिंह सोलर बुक्स 1 जनवरी 2017 पृ. सं. 78.
16. सिंह पंकज के., स्वच्छ भारत समृद्ध भारत डायमंड बुक्स 1 अक्टूबर 2015
17. भारत में स्वच्छ अभियान कार्य नीति और – क्रियान्वयन नेशनल बुक ट्रस्ट 1 जनवरी 2016

